



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

Nov-2000

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 4 नवम्बर, 2000/13 कार्तिक, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 3 नवम्बर, 2000

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (1) 9/2000-26646-72.—संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्या 4) के प्रावधानों के अनुरूप जिला परिषदों अधिकांश पदों के लिए आरक्षण किया जाना तथा इन अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् कराए जाने वाले प्रथम निर्वाचन के बाद आरक्षित पदों को राज्य के भिन्न-भिन्न निर्वाचित क्षेत्रों में चक्रानुक्रम अनुसार आवंटन किया जाना अनिवार्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1991 के नियम 89 के उप-नियम (1) तथा (9) के प्रयोग हेतु, हिमाचल प्रदेश की जिला परिषदों के अधिकांश पदों का निर्धारण एवं इन पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए संलग्न अनुमूर्ची में दिए गए विवरणानुसार आरक्षित करने के महर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

जिला परिषद का नाम जिसके अध्यक्ष पद को आरक्षित किया जाता है

प्रदेश में जिला/जिला
परिषद का नाम

अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		सामान्य महिला
सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
2	3	4	5	6	7	8

1. बिलासपुर	1. बिलासपुर	1. मण्डी	1. किन्नौर	1. लाहौल-स्पति	—	1. ऊना	1. चम्बा
2. चम्बा	2. शिमला						
3. हमीरपुर							
4. कांगड़ा							
5. किन्नौर							
6. कुल्लू							
7. लाहौल-स्पति							
8. मण्डी							
9. शिमला							
10. सोलन							
11. विरमौर							
12. ऊना							

सूची"

जिला परिषदों की संख्या का निर्धारण जिनके अध्यक्ष पदों को विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित किया गया है

जिला परिषद् का नाम जहाँ अध्यक्ष का पद अनारक्षित होगा	अनुसूचित जाति सामान्य	अनुसूचित जनजाति सामान्य	पिछड़ा वर्ग सामान्य	महिला वर्ग			
	10	11	12	अनुसूचित जाति 13	अनुसूचित जनजाति 14	पिछड़ा वर्ग 15	सामान्य 16
1. हमीरपुर	2	1		1	1	1	1
2. कांगड़ा							
3. कुल्लू							
4. सोलन							
5. सिरमौर							

